सहायक कृषि आयकर आयुक्त एवं अन्य

बनाम

मैसर्स नेटली 'बी' एस्टेट और अन्य

(2003 की सिविल अपील संख्या 8617-8635)

17 मार्च, 2015

[ न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन]

*कर्नाटक कृषि आयकर अधिनियम, 1957।–धारा 26(4) स्पष्टीकरण–धारा 26(4) में पूर्वव्यापी रूप से जोड़ी गई स्पष्टीकरण की वैधता–कृषि आय का आकलन– किसी फर्म के विघटन के बाद उसे प्राप्त होने वाली राशि, जहां तक फर्म की आय का संबंध है, फर्म के विघटन के बाद वास्तविक नकदी प्राप्तियों से संबंधित है, लेकिन विघटन से पहले अर्जित आय से संबंधित है– एल.पी. कार्डोज़ा मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि एक विघटित फर्म को उसके विघटन से पहले फर्म द्वारा की गई वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त आय के संबंध में उसके विघटन की तारीख के बाद कृषि आयकर का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विघटन के बाद फर्म को कोई अस्तित्व नहीं और धारा 26(4) केवल एक फर्म के व्यवसाय को बंद करने के लिए संदर्भित है, न कि किसी फर्म के विघटन के लिए– इसके बाद धारा 26(4) में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन, 01.04.1975 से–को चुनौती– उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पूर्वव्यापी संशोधन को बरकरार रखा– डी. कैवासजी मामले के बाद खंड पीठ ने माना कि संशोधन का उद्देश्य कार्डोज़ा के मामले को पूर्ववत करना था, इस प्रकार, यह असंवैधानिक था– अपील पर, अभिनिर्धारित: 01.04.1975 से, विघटित फर्मों का कृषि आयकर लगाने और संग्रह करने के प्रयोजनों के लिए, कानूनी रूप से*

*मूल्यांकन किया जाना जारी रहेगा, जहां तक कि वे विघटन के बाद आय प्राप्त करते हैं, लेकिन विघटन से पहले के लेनदेन से संबंधित हैं– विधायिका ने कार्डोज़ा के मामले में फैसले को सीधे रद्द करने की मांग नहीं की है– कानूनी आधार जिस पर कार्डोज़ा का मामला बनाया गया था, उसे पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया गया है, जो विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर है– कार्डोज़ा के मामले में न्यायिक निर्णय को विधायी क्षेत्र के भीतर एक विषय पर एक वैध कानून बनाकर अप्रभावी बना दिया गया है जो मूल रूप से कानून के चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तित कर देता है या बदल देता है– परिवर्तित या बदली हुई स्थितियाँ ऐसी हैं कि यदि कानून को अवैध घोषित करने के समय वे स्थितियाँ मौजूद होतीं तो न्यायालय द्वारा पिछला निर्णय नहीं दिया जाता– विधायिका ने सीधे तौर पर फैसले को खारिज नहीं किया, बल्कि जिस आधार पर फैसला लिया गया था, उसे हटाकर ऐसे फैसले को अप्रभावी बना दिया है– इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया गया।*

डी. कावासजी एंड कंपनी, मैसूर बनाम मैसूर राज्य और अन्य 1985 एससीआर 825: 1984 (पूरक) एससीसी 490; पंछी देवी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2008 (17) एससीआर 1325: (2009) 2 एससीसी 589; टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2004 (2) पूरक एससीआर 452:(2004) 5 एससीसी 783; हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 2006 (7) पूरक एससीआर 766: (2006) 8 एसईसी 613–पृथक किया गया।

एलपी कार्डोज़ा और अन्य बनाम कृषि आयकर अधिकारी और अन्य (1997) 227 आईटीआर 421; श्री रंगा मैच इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1994 (पूरक) 2 एससीसी 726; इंडियन एल्युमीनियम कंपनी और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य 1996 (2) एससीआर 23: (1996) 7 एससीसी 637–संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

| | | |
|---|---|---|
| (1997) 227 आईटीआर 421 | संदर्भित किया गया | पैरा 4 |
| 1985 एससीआर 825 | पृथक किया गया | पैरा 16 |
| 1994 (पूरक) 2 एससीसी 726 | संदर्भित किया गया | पैरा 17 |
| 1996 (2) एससीआर 23 | संदर्भित किया गया | पैरा 18 |
| 2008 (17) एससीआर 1325 | पृथक किया गया | पैरा 21 |
| 2004 (2) पूरक एससीआर 452 | पृथक किया गया | पैरा 22 |
| 2006 (7) पूरक एससीआर 766 | पृथक किया गया | पैरा 23 |

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 8617-8635/2003

कर्नाटक उच्च न्यायालय के खंड पीठ के 1998 की रिट याचिका सं 3795 से 3809 में और 1997 की सी.आर.पी. सं 633 और 634 में दिनांक 03.07.2002 के निर्णय और आदेश से।

वी. एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगाड़ी, संजय आर. हेगड़े अपीलार्थियों के लिए।

जी. सारंगन, संजय कुमार, आर. एन. केशवानी उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन

1. अपीलों का वर्तमान समूह कर्नाटक कृषि आयकर अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 26(4) में पूर्वव्यापी रूप से जोड़े गए स्पष्टीकरण की वैधता से संबंधित है।

2. तथ्यों के आधार पर, वर्तमान अपीलें किसी फर्म के विघटन के बाद प्राप्त कृषि आय के आकलन से संबंधित हैं, जहां तक फर्म की आय फर्म के विघटन के बाद वास्तविक नकदी प्राप्तियों से संबंधित है, लेकिन विघटन से पहले अर्जित आय से संबंधित है।

अधिनियम की धारा 26 इस प्रकार है:

"26. बंद कंपनी, फर्म या एसोसिएशन के मामले में मूल्यांकन -

(1) जहां कृषि आय किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा प्राप्त की जाती है और जिस व्यवसाय के माध्यम से ऐसी आय प्राप्त होती है वह किसी भी वर्ष बंद हो जाती है, पिछले वर्ष के अंत और इस तरह के समापन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान प्राप्त कृषि आय के आधार पर उस वर्ष में मूल्यांकन किया जा सकता है, पिछले वर्ष प्राप्त कृषि आय के आधार पर किए गए मूल्यांकन, यदि कोई हो, के अतिरिक्त।

(2) ऐसे किसी भी व्यवसाय को बंद करने वाला कोई भी व्यक्ति कृषि आयकर अधिकारी को तीस दिनों के भीतर इस तरह के बंद होने का नोटिस देगा और जहां कोई भी व्यक्ति इस उप-धारा द्वारा आवश्यक नोटिस देने में विफल रहता है, तो ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है कि व्यवसाय बंद होने की तारीख तक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ की किसी भी कृषि आय के संबंध में बाद में उस पर निर्धारित कृषि आयकर की राशि से अधिक नहीं होने वाले जुर्माने के माध्यम से एक राशि उससे वसूल कि जाएगी।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत मूल्यांकन किया जाना है, कृषि आयकर अधिकारी उस व्यक्ति पर जारी कर सकता है जिसकी कृषि आय का मूल्यांकन किया जाना है, या, किसी फर्म के मामले में किसी भी व्यक्ति पर जारी कर सकता है समाप्ति के समय

ऐसी फर्म का एक सदस्य या, किसी कंपनी के मामले में, उसके प्रमुख अधिकारी को, एक नोटिस जिसमें सभी या कोई भी आवश्यकताएं शामिल होती हैं, जिन्हें धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस में शामिल किया जा सकता है और इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि नोटिस उस उप-धारा के तहत जारी किया गया नोटिस था।"

3. 1987 में संशोधन द्वारा धारा 26 में उप-धारा (4) जोड़ी गई और इसे इस प्रकार पढ़ा गया: -

"जहां कोई भी व्यवसाय जिसके माध्यम से कृषि आय प्राप्त होती है, उसे किसी भी वर्ष बंद कर दिया जाता है, बंद होने के बाद प्राप्त किसी भी राशि को प्राप्तकर्ता की आय माना जाएगा और प्राप्ति के वर्ष के अनुसार कर लगाया जाएगा, अगर ऐसी राशि इस तरह के बंद होने से पहले प्राप्त हुई होती तो वह राशि व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल की गई होती।"

4. धारा 27 जिससे हम भी संबंधित हैं, इस प्रकार है:-

"27. बंद की गई फर्म या संघ के मामले में दायित्व - (1) जहां किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है या ऐसी फर्म या संघ को भंग कर दिया जाता है, कृषि आयकर के सहायक आयुक्त फर्म या व्यक्तियों के संघ की कृषि आय का आकलन इस प्रकार करेंगे जैसे कि ऐसा कोई विच्छेदन या विघटन नहीं हुआ है और इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत जुर्माना या किसी अन्य राशि के आरोपण से संबंधित सभी प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे मूल्यांकन पर लागू होंगे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे विच्छेदन या विघटन के समय, ऐसी फर्म का भागीदार या ऐसे संघ का सदस्य और ऐसे किसी भी व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि, जो मर चुका है,

ऐसी कृषि आय पर मूल्यांकन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा और कृषि आयकर की राशि, जुर्माना या अन्य देय राशि का भुगतान करने के लिए और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे किसी भी मूल्यांकन या जुर्माना या अन्य राशि लगाने पर लागू होंगे।"

5. धारा 27 के साथ पढ़ी गई धारा 26(4) के सरसरी तौर पर पढ़ने से, यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी फर्म द्वारा व्यवसाय बंद करने के बाद प्राप्त कोई भी राशि प्राप्तकर्ता की आय मानी जाती है और तद्नुसार कर लगाया जाएगा, यदि ऐसी राशि उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल की गई होती जिसने व्यवसाय चलाया था, यदि ऐसी राशि इस तरह के बंद होने से पहले प्राप्त हुई थी। धारा 27 में एक कदम आगे बढ़ कर ऐसी फर्म की आय के बारे में भी बताया गया है जो विघटित हो गई है, न कि उस फर्म की आय के बारे में जिसका व्यवसाय बंद कर दिया गया है। ऐसी आय के संबंध में, प्रत्येक व्यक्ति, जो समाप्ति या विघटन के समय, ऐसी फर्म का भागीदार था, ऐसी कृषि आय पर संयुक्त रूप से या अलग-अलग मूल्यांकन करने के साथ-साथ कर दंड आदि के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

6. एल.पी. कार्डोज़ा और अन्य बनाम कृषि आयकर अधिकारी और अन्य [(1997) 227 आईटीआर 421] में, यह सवाल शामिल था कि क्या एक विघटित फर्म पर उसके विघटन से पहले फर्म द्वारा की गई वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त आय के संबंध में उसके विघटन की तारीख के बाद कृषि आयकर का आकलन किया जा सकता है। यह प्रश्न धारा 26(4) और धारा 27 के आलोक में तब उठा, जैसे वे उस समय थे, अर्थात, जैसे वे 1987 में थे। उपरोक्त प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद पीठ द्वारा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया: -

"इसलिए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि धारा 27 के तहत विघटित फर्म को फर्म के विघटन की तारीख के बाद प्राप्त आय के संबंध में मूल्यांकन के उद्देश्य से अस्तित्व में माना जा सकता है। वास्तव में 1988 की डब्ल्यू.पी. संख्या 2397 और 2398 में कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण ने यही विचार अपनाया था और इसी आधार पर मूल्यांकन आदेशों को रद्द कर दिया गया था।

विचार करने योग्य अगला बिंदु यह है कि क्या 1987 के अधिनियम 10 द्वारा संशोधित धारा 26(4), प्रतिवादी के लिए कोई मदद कर सकती है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि धारा 26(4) केवल व्यवसाय को बंद करने के मामले पर लागू होती है, न कि फर्म के विघटन के मामले में, धारा 27 किसी व्यवसाय को बंद करने और फर्म के विघटन के बीच अंतर करती है, और इस प्रकार धारा 26(4) फर्म के विघटन के मामले पर लागू नहीं होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कारोबार बंद होने से जरूरी नहीं कि कंपनी का विघटन हो जाए। एक फर्म अस्तित्व में बनी रह सकती है लेकिन किसी विशेष व्यवसाय को चलाना बंद कर सकती है। लेकिन जब कोई फर्म भंग हो जाती है तो इसमें आवश्यक रूप से व्यवसाय का बंद होना शामिल होता है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 26(4) को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह फर्म के विघटन का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन हम इस बात से संबंधित हैं कि क्या यह प्रावधान विघटन के बाद प्राप्त आय का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी के विघटन के बावजूद उसकी निरंतरता के संबंध में कोई कानूनी कल्पना पैदा करता है। यह प्रावधान केवल इतना कहता है कि, व्यवसाय बंद करने के बाद प्राप्त कोई भी राशि "प्राप्तकर्ता" की आय मानी जाएगी और प्राप्ति के वर्ष में कर लगाया जाएगा, यदि ऐसी राशि उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल की गई होती जिसने व्यवसाय चलाया होता, यदि ऐसी राशि ऐसे बंद होने से पहले प्राप्त हुई होती। इस प्रावधान को समझाते हुए ई.एम.वी. मुथप्पन

(1990) 184 आईटीआर 161 के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ ने बताया है कि चूंकि प्राप्त बिक्री आय पिछले वर्षों के दौरान की गई कृषि गतिविधि से संबंधित आय है, इसलिए इसे प्राप्तकर्ता की आय माना जाना चाहिए, क्योंकि मूल निर्धारिती अब व्यवसाय जारी नहीं रख रहा है और इसलिए, प्राप्तकर्ता के हाथ में प्राप्ति के वर्ष में कर के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान उस मामले पर लागू होता है जहां व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति इसे बंद कर देता है और उसके मूल निर्धारती होने के नाते उसे देय आय व्यवसाय बंद होने के बाद दूसरे को प्राप्त होती है। ऐसे मामले में, प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आय पर प्राप्ति के वर्ष में कर लगाया जा सकता है। <u>इस प्रावधान में यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जहां फर्म विघटित हो गई है और विघटन से पहले फर्म द्वारा आपूर्ति की गई कृषि उपज के संबंध में विघटन के बाद कुछ आय प्राप्त होती है, तो फर्म का मूल्यांकन उसके विघटन के बावजूद आय प्राप्ति के वर्ष में किया जा सकता है।"</u>

7. इस फैसले को पढ़ने पर दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अधिनियम की धारा 27 न्यायालय के समक्ष प्रश्न का उत्तर देने में मदद नहीं करेगी क्योंकि विघटन के बाद एक फर्म का कानून की नजर में कोई अस्तित्व नहीं है और इस कारण से वह निर्धारिती नहीं हो सकती है। दूसरे, धारा 26(4) ने भी इसी कारण से मदद नहीं की और इसलिए भी कि यह किसी फर्म के विघटन के विपरीत केवल एक फर्म के व्यवसाय को बंद करने का संदर्भ देता है।

8. न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि धारा 26(4) में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे कि यह तब मौजूद थी या धारा 27 में यह इंगित करने के लिए कि जहां फर्म विघटित हो गई है और विघटन से पहले फर्म द्वारा आपूर्ति की गई कृषि उपज के संबंध में विघटन के बाद आय प्राप्त होती है, तो विघटन के बावजूद फर्म का मूल्यांकन आय प्राप्ति के वर्ष में किया जा सकता है।

9. कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फैसले का सामना करते हुए, विधायिका ने धारा 26(4) को पूर्वव्यापी रूप से, यानी 01.04.1975 से संशोधित किया। संशोधित प्रावधान अब इस प्रकार है:-

"26(4) जहां कोई व्यवसाय जिसके माध्यम से किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ को कृषि आय प्राप्त होती है, बंद कर दिया जाता है या ऐसी कोई फर्म या संघ किसी भी वर्ष में भंग कर दिया जाता है, तो समाप्ति या विघटन के बाद प्राप्त किसी भी राशि को प्राप्तकर्ता की आय माना जाएगा और प्राप्ति के वर्ष में तदनुसार ऐसे कर लगाया जाएगा, यदि ऐसी राशि उस व्यवसाय को चलाने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल की गई होती, यदि ऐसी राशि ऐसे बंद होने या विघटन से पहले प्राप्त हुई होती।

स्पष्टीकरण: - संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस तरह के व्यवसाय को बंद करने या किसी फर्म या संघ के विघटन से पहले एक फर्म या संघ के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, या जैसा भी मामला हो कंपनी पर, फसल की कटाई और निपटान किया जाता है लेकिन ऐसी फसल के लिए पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, या फसल की कटाई की जाती है और उसका निपटान नहीं किया जाता है, ऐसी फसल से होने वाली आय, समाप्ति या विघटन के बावजूद उस कंपनी, फर्म या संघ की आय मानी जाएगी उस वर्ष या वर्षों के लिए जिसमें यह प्राप्त या प्राप्य है और फर्म या एसोसिएशन को ऐसे वर्ष या वर्षों के लिए अस्तित्व में माना जाएगा और ऐसी आय का मूल्यांकन कंपनी, फर्म या संघ की आय के रूप में ऐसे समाप्ति या विघटन से तुरंत पहले नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार किया जाएगा।"

10. यह देखा जाएगा कि संशोधित धारा 26(4) में, दो बदलाव किए गए हैं। जबकि मूल प्रावधान में, कंपनियों या व्यक्तियों के संघों का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं

दिया गया था और किसी विघटित फर्म का भी कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, अब दोनों को जोड़ दिया गया है। स्पष्टीकरण द्वारा, जो संदेह को दूर करने के लिए है, विधायिका घोषणा करती है कि जहां किसी फर्म के विघटन से पहले उस आय के संबंध में पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं होता है जो विघटन से पहले अर्जित किया गया है, तो ऐसे विघटन के बावजूद, उक्त आय उस वर्ष में फर्म की आय मानी जाएगी जिसमें यह प्राप्त या प्राप्य है और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए फर्म को ऐसे वर्ष के लिए अस्तित्व में माना जाएगा। इस संशोधन के द्वारा यह देखा जाएगा कि जो कानून का आधार कार्डोज़ा के मामले का फैसला आने के समय मौजूद था, बदल दिया गया है।

11. कार्डोज़ा के मामले में देखा गया कि ऐसी कोई मान लेने वाली प्रक्रिया नहीं थी जो विघटित हो चुकी किसी फर्म को उस आय के प्रयोजनों के लिए करदाता के रूप में जारी रखती हो जो कि विघटन से पहले अर्जित की गई थी लेकिन विघटन के बाद प्राप्त हुई थी। मान लेने की कल्पना को अब स्पष्टीकरण द्वारा (और 1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) पेश किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि कानून का आधार जो कार्डोज़ा के मामले का फैसला होने के समय था, अब 1975 से बदल दिया गया है। इसलिए, जो स्थिति उभरती है वह यह है कि ऐसी आय पर "प्राप्तकर्ता" के हाथों कर लगाने के बजाय, अब इस पर विघटित फर्म के हाथों कर लगाया जाता है।

12. उक्त संशोधन कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती का विषय था। एकल न्यायाधीश ने मूल रूप से इस आधार पर चुनौती को खारिज कर दिया कि स्पष्टीकरण केवल मुख्य प्रावधान को स्पष्ट करता है और इसलिए मुख्य प्रावधान से आगे नहीं जाता है। समान रूप से, चूंकि विधायिका को संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से संशोधन करने का अधिकार है, वर्तमान मामले में जो कुछ भी किया गया वह पूर्वव्यापी रूप से विधायी शक्ति का प्रयोग था और

इसलिए, इस संबंध में किसी भी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए एकल न्यायाधीश ने उनके समक्ष दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

13. खंड पीठ के समक्ष अपील में, खंड पीठ ने उपरोक्त सभी प्रावधानों को निर्धारित किया और अंततः डी. कावासजी एंड कंपनी, मैसूर बनाम मैसूर राज्य और अन्य [1984 (पूरक) एससीसी 490] में फैसले के बाद पाया कि 1997 का संशोधन अधिनियम कावासजी के मामले में पाए गए दोष से ग्रस्त था, अर्थात् यह सीधे तौर पर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करता है और इसलिए, केवल इसी आधार पर इसे असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। ऐसा खंड पीठ ने इसलिए पाया क्योंकि खंड पीठ के अनुसार, 1997 के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के बयान में यह माना गया था कि संशोधन का उद्देश्य कार्डोज़ा के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को पूर्ववत करना था।

14. राजस्व हमारे समक्ष अपील में है। विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि कावासजी के मामले में तथ्यात्मक स्थिति वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति से पूरी तरह से अलग थी और इसलिए, कावासजी के मामले में अंतर होने के कारण, इसका पालन नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने कई अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिन पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। इस दलील को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर जो कुछ किया गया वह यह था कि विधायिका ने कंपनियों के विघटन के बाद प्राप्त आय के संबंध में उनके मूल्यांकन के कानून के आधार को पूर्वव्यापी रूप से बदल दिया, जो कि विधायिका करने के लिए सक्षम है।

15. दूसरी ओर, निर्धारितियों के विद्वान वकील ने फैसले का समर्थन करने की कोशिश की। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि चूँकि, वास्तव में कोई कमी दूर नहीं

की जानी थी, इसलिए पूर्वव्यापी संशोधन की विधायी प्रक्रिया ख़राब होगी क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि एक स्पष्टीकरण उस मूल प्रावधान को पराजित नहीं कर सकता जिससे वह जुड़ा हुआ है और इसलिए वर्तमान स्पष्टीकरण, मुख्य प्रावधान से परे होने के कारण भी खराब है। उन्होंने कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया जिनका हम उल्लेख करेंगे।

16. सबसे पहले, कावासजी के मामले में निर्णय। कावासजी के मामले में निर्णय के लिए जो प्रश्न आया वह मैसूर बिक्री कर अधिनियम, 1957 में किया गया एक पूर्वव्यापी संशोधन था, जिसमें बिक्री कर को पूर्वव्यापी रूप से 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके विपरीत किसी भी निर्णय के बावजूद, भले ही बिक्री कर का संग्रह इस आधार पर कम कर दिया गया है कि उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर बेची गई ताड़ी की कीमत में शामिल नहीं किया जा सकता है, फिर भी ऐसा कर कानून के अनुसार वैध रूप से लगाया और एकत्र किया गया माना जाएगा। निर्णय का अनुपात निर्णय के पैराग्राफ 18 से सामने आता है जिसे यहाँ नीचे दिया गया है: -

"वर्तमान मामले में, राज्य ने दोष को दूर करने या कमी को दूर करने के बजाय एकत्रित अतिरिक्त राशि को वापस करने की देनदारी से बचने के लिए आक्षेपित संशोधन द्वारा 1 अप्रैल, 1966 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कर की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने की मंशा की है और अवैध रूप से एकत्र की गई अतिरिक्त राशि की वापसी का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश को रद्द करने के इरादे से यह प्रावधान किया कि 45 प्रतिशत की उच्च दर पर आरोपण 1 अप्रैल, 1966 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर पर बिक्री कर लगाने को गलत घोषित करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय निर्णायक हो गया है और पक्षों के लिए बाध्यकारी है। उत्पाद शुल्क, शिक्षा

उपकर और स्वास्थ्य उपकर पर किसी भी संशोधन के माध्यम से बिक्री कर लगा करके कमियों को दूर करना और पहले के कर में दोष को दूर करना यह राज्य विधानमंडल के लिए वैध रूप से सक्षम हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन, किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार ने संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा करने का इरादा नहीं किया है। उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के कर को अवैध घोषित करने के फैसले के परिणामस्वरूप, राज्य पिछले फैसले में उस आशय के विशिष्ट निर्देश के आधार पर गलत तरीके से और अवैध रूप से एकत्र की गई अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए बाध्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधित प्रावधान को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य निर्णय के प्रभाव को खत्म करना है जो पार्टियों पर निर्णायक और बाध्यकारी हो गया है ताकि राज्य सरकार गलत तरीके से और अवैध रूप से बिक्री कर के रूप में एकत्र की गई राशि को अपने पास रख सके और इस उद्देश्य को आक्षेपित संशोधन द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की गई है, जो दोष और खामियों को दूर करने या सुधारने का इरादा भी नहीं रखता है, बल्कि शुल्क की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर देता है और आगे बढ़कर उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द कर देता है। हमारी राय में, पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है। दोष या कमी को दूर करने की कोशिश भी नहीं की गई है और संशोधित प्रावधान द्वारा शुल्क की दर में भारी वृद्धि का एकमात्र औचित्य बाध्यकारी निर्णय के प्रभाव को समाप्त करना है। अवैध वसूली का दोष उस अवैधता को हटाने के अभाव में जिसके कारण अवैध करारोपण के आधार पर पहले के आकलन अमान्य हो गए, पहले के आरोपण को कलंकित करना जारी रखता है। हमारी राय में, पूर्वव्यापी प्रभाव से उच्च दर पर करारोपण का यह उचित आधार नहीं है। भावी परिचालन के साथ उच्च दर पर कर लगाने के लिए विधायिका स्वतंत्र हो सकती है, लेकिन उच्च दर पर कराधान

लगाना जो वास्तव में पूर्वव्यापी संचालन के साथ कर लगाने के समान है को उचित और ठोस आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया है और हमारे विचार में उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि "आक्षेपित अधिनियम की धारा 2 के अधिनियमन द्वारा, पिछली रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का मूल आधार और कावासजी मामले में इस न्यायालय के निर्णय का आधार भी कि राज्य अधिनियम के तहत अधिकृत राशि से अधिक राशि कर के रूप में एकत्र कर रहा है, उसे हटा दिया गया है।" तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को उस हद तक रद्द करते हैं, जिस हद तक यह 1 अप्रैल, 1966 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू संशोधन की वैधता को बरकरार रखता है और जिस हद तक यह उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को रद्द करना चाहता है। हम घोषित करते हैं कि आक्षेपित संशोधन की धारा 2 इस हद तक कि यह 1 अप्रैल 1966 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 45 प्रतिशत की उच्च करारोपण करती है और आक्षेपित अधिनियम की धारा 3 जो उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द करने की मांग करती है, अमान्य और असंवैधानिक हैं।"

17. इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि पूर्वव्यापी कर को रद्द करने के लिए दो कारण दिए गए थे। पहला कारण यह दिया गया कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पूर्वव्यापी रूप से शुल्क की वसूली को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करना अपने आप में मनमाना और अनुचित है। दूसरा कारण यह दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई कमी या खामी को दूर करने की कोशिश नहीं की गई है और शुल्क की दर में भारी वृद्धि का एकमात्र औचित्य पहले के बाध्यकारी फैसले के प्रभाव को खत्म करना है। यह माना गया कि अवैध वसूली को हटाने के

अभाव में अवैध वसूली की बुराई, जिसके कारण पहले का करारोपण अमान्य हो गया था, पहले के आरोपण को कलंकित करता रहा।

18. यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह अलग है। वर्तमान मामले में जो कुछ भी किया गया है वह कानून के आधार को जैसा कि 1987 में था, जिसकी व्याख्या कार्डोज़ा के मामले में एक विशेष परिणाम के रूप में की गई थी, को हटाने के लिए किया गया है। वर्तमान मामले में विधायिका ने जो कुछ किया है वह यह है कि 01.04.1975 से प्रभावी, विघटित फर्मों का कृषि आय कर लगाने और संग्रह करने के प्रयोजनों के लिए कानूनी कल्पना के अनुसार मूल्यांकन जारी रहेगा, जहां तक कि वे विघटन के बाद आय प्राप्त करती हैं लेकिन विघटन पूर्व लेनदेन से संबंधित हैं। वर्तमान मामले में विधायिका ने किसी भी तरह से कार्डोज़ा के मामले में फैसले को सीधे रद्द करने की मांग नहीं की है। जो कुछ हुआ है वह यह है कि जिस कानूनी आधार पर कार्डोज़ा का मामला बनाया गया था उसे पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया गया है, जो विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर है।

19. श्री रंगा मैच इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [1994 (पूरक) 2 एससीसी 726] में इस अदालत ने एक क़ानून के पूर्वव्यापी सत्यापन की उसी स्थिति से निपटा, जिसे अन्यथा असंवैधानिक घोषित किया गया था। कैवासजी का मामला जिस पर वहां भरोसा किया गया था (जैसा कि वर्तमान मामले में इस पर भरोसा किया गया है) निम्नलिखित शर्तों में विशिष्ठ था:-

"इस स्तर पर, डी. कावासजी एंड कंपनी, मैसूर बनाम मैसूर राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले से निपटना उचित होगा, जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री वैद्यनाथन ने भी भरोसा जताया था, शराब पर बिक्री कर 6 प्रतिशत लगाया गया था। सरकार इसे ताड़ी के पूरे विक्रय मूल्य पर वसूल रही थी। हालाँकि, लाइसेंसधारियों

द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि बिक्री मूल्य के उत्पाद शुल्क और उपकर घटक पर बिक्री कर लगाना अक्षम्य था। दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि बिक्री कर केवल उचित कीमत पर लगाया जा सकता है, लेकिन उत्पाद शुल्क और उपकर पर नहीं, जो बिक्री मूल्य का हिस्सा है। इस न्यायालय में उच्च न्यायालय के उक्त फैसले पर सवाल उठाया गया था लेकिन बाद में सरकार ने अपील वापस ले ली, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम हो गया। रिफंड के दावों को रद्द करने की दृष्टि से, कर्नाटक विधानमंडल ने हस्तक्षेप किया और पूर्वव्यापी प्रभाव से मैसूर बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किया। संशोधित अधिनियम ने कर की दर 6% से बढ़ाकर 45% कर दी, जिसका अर्थ था कि सरकार को उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार लाइसेंसधारियों को कोई राशि वापस करने की आवश्यकता नहीं थी। संशोधन अधिनियम पर उच्च न्यायालय में सवाल उठाया गया लेकिन उसे बरकरार रखा गया। अपील पर, इस न्यायालय ने संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया। फैसले को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि मुख्य आधार जिस पर अधिनियम को अक्षम माना गया था, वह यह था कि पूर्वव्यापी प्रभाव से कर की दर को 6% से बढ़ाकर 45% करना "स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित" था और इसलिए अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन था। यह देखा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दोष/कमियों को दूर करने के बजाय, विधायिका ने पूर्वव्यापी प्रभाव से कर की दर को तेजी से बढ़ाने की मांग की और यह खराब था। फैसले को इसे निर्धारित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि विधायिका किसी भी स्थिति में उस दोष या कमी को संशोधित या सुधार कर न्यायालय के फैसले को अप्रभावी और निष्क्रिय करने की कोशिश नहीं कर सकती है, जिसके आधार पर निर्णय दिया गया था। इसलिए, मेरी राय में, उक्त निर्णय को अपीलकर्ता की दलील का समर्थन करने के रूप में नहीं समझा जा सकता है और न ही इसे संसद की अच्छी तरह से स्वीकृत

शक्ति के खिलाफ उल्लंघन के रूप में पढ़ा जा सकता है, जिसे इस न्यायालय के असंख्य निर्णयों में दोहराया गया है।"

20. भारतीय एल्युमीनियम कंपनी और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [(1996) 7 एससीसी 637] मामले में, सत्यापन अधिनियमों पर बड़ी संख्या में निर्णयों के साथ एक लंबी चर्चा हुई है। कावासजी के मामले को पैरा 52 में निम्नलिखित शर्तों में निपटाया गया था:

"डी. कावासजी एंड कंपनी बनाम मैसूर राज्य में अपीलकर्ता द्वारा दायर एक रिट में उच्च न्यायालय ने माना था कि राज्य सरकार बिक्री कर अधिनियम की धारा 19 के तहत बिक्री कर और उत्पाद शुल्क एकत्र करने की शक्ति से वंचित थी जो बिक्री मूल्य का हिस्सा नहीं है। रिफंड हेतु परमादेश जारी किया गया। इस न्यायालय में दायर अपील वापस ले ली गई और बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव से बिक्री कर को मूल 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया। धारा 3 ने पिछले आकलन को मान्य किया। इस न्यायालय ने संशोधन को जहां तक यह पूर्वव्यापीता से संबंधित था, यह इंगित करते हुए खारिज कर दिया कि अदालत द्वारा बताई गई खामी को ठीक नहीं किया गया था और फैसले को विधायी संशोधन द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता था।"

21. अंत में, पैरा 56 में निम्नानुसार कई सिद्धांत निर्धारित किए गए:-

"उपरोक्त निर्णयों के सारांश से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आएंगे:

(1) पक्षों के अधिकारों का निर्णय आवश्यक न्यायिक कार्य है। विधानमंडल को आचरण के मानदंड या नियम निर्धारित करने होंगे जो पक्षों और लेनदेन को नियंत्रित करेंगे और अदालत को उन्हें प्रभावी करने की आवश्यकता होगी;

(2) संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग में नाजुक संतुलन की रूपरेखा तैयार की;

(3) कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, विधायिका कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 245 और 246 और सातवीं अनुसूची में संबंधित सूचियों में प्रविष्टियों के साथ पढ़े जाने वाले अन्य सहयोगी लेखों के तहत शक्ति का प्रयोग करती है जिसमें कानून में संशोधन करने की शक्ति शामिल है।

(4) न्यायालयों को अपने संबंध में और न्यायिक शक्ति को संरक्षित करने के प्रयास में और तीन संप्रभु पदाधिकारियों के बीच संविधान द्वारा तैयार किए गए नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। कानून के शासन द्वारा समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा कर सकने के उद्देश्य से, संबंधित संप्रभु पदाधिकारियों को अपने जोड़ों में स्वतंत्र क्रियाशीलता की आवश्यकता है ताकि सामाजिक प्रगति और व्यवस्था की प्रगति निर्बाध बनी रहे। विनम्रता से निर्मित सहज संतुलन हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए

(5) न्यायिक शक्ति की रक्षा करने की चिंता में, अत्यधिक उत्साही होना और सक्षम रूप से बनाए गए वैध कानून को अमान्य करने के लिए न्यायिक संरक्षण में घुसपैठ करना अनावश्यक है;

(6) इसलिए, अदालत को यह पता लगाने के लिए कानून का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है; (ए) क्या अदालत द्वारा बताई गई बुराई और पिछले कानून द्वारा झेली गई अमान्यता कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए ठीक हो गई है; (बी) क्या विधायिका के पास कानून को मान्य करने की क्षमता है; (सी) क्या ऐसी मान्यता संविधान के भाग III में गारंटीकृत अधिकारों के अनुरूप है।

(7) अदालत के पास किसी अमान्य कानून को मान्य करने या अवैध रूप से बनाए और एकत्र किए गए कर को वैध बनाने या अमान्यता के मानदंड को हटाने या कोई उपाय प्रदान करने की शक्ति नहीं है। ये न्यायिक कार्य नहीं हैं बल्कि विधायिका के विशिष्ट प्रांत हैं। इसलिए, वे न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं।

(8) विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका केवल घोषणा के द्वारा, बिना किसी और बात के, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे तौर पर खारिज, संशोधित या रद्द नहीं कर सकती है। यह अपने विधायी क्षेत्र के भीतर इस विषय पर वैध कानून बनाकर मौलिक रूप से परिवर्तन करके या इसके चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से बदलकर न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बना सकती है। परिवर्तित या बदली हुई स्थितियाँ ऐसी हैं कि पिछला निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया होता, यदि कानून को अमान्य घोषित करने के समय वे स्थितियाँ मौजूद होतीं। इसे पूर्वव्यापी कानून को एक विचारणीय तिथि के साथ या किसी विशेष तिथि से प्रभावी बनाने का भी अधिकार है। विधायिका कर या शुल्क के चरित्र को गैर अनुमेय से अनुमेय कर में बदल सकती है लेकिन कर या करारोपण को ऐसी भूमिका में ठीक बैठना चाहिए और विधायिका विषय से वसूली के लिए अमान्य आधार को हटाने या राज्य से वसूली को अप्रभावी बनाने पर ऐसे कर को मान्य करते हुए अमान्य कर की वसूली करने में सक्षम है। विधायिका के लिए यह सक्षम है कि वह पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाए और अपनी एजेंसियों को उस आधार पर कर लगाने और एकत्र करने के लिए अधिकृत करे, वसूले गए कर के अधिरोपण और कर की वसूली को अदालत की घोषणा या उसकी वसूली के लिए दिया गये निर्देश के बावजूद वैध बनाए।

(9) इस न्यायालय के सभी निर्णयों के माध्यम से चलने वाला सुसंगत सूत्र यह है कि विधायिका सीधे निर्णय को खारिज नहीं कर सकती है या उस पर बाध्यकारी नहीं होने का कोई निर्देश नहीं दे सकती है, लेकिन संविधान के कानून के अनुरूप जिस

आधार पर निर्णय दिया गया था, उसे हटाकर निर्णय को अप्रभावी बनाने की शक्ति है और विधायिका के पास ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए।"

22. हम इस मामले में सीधे सिद्धांत 8 और 9 से संबंधित हैं। तथ्यों पर, कार्डोज़ा के मामले में न्यायिक निर्णय को विधायी क्षेत्र के भीतर एक विषय पर एक वैध कानून बनाकर अप्रभावी बना दिया गया है जो मूल रूप से कानून के चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तित करता या बदल देता है। बदली हुई या परिवर्तीती स्थितियाँ ऐसी हैं कि यदि कानून को अमान्य घोषित करने के समय वे स्थितियाँ मौजूद होतीं तो न्यायालय द्वारा पिछला निर्णय नहीं दिया जाता। विधायिका ने सीधे तौर पर किसी भी न्यायालय के फैसले को खारिज नहीं किया है, बल्कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, केवल उस आधार को हटाकर ऐसे फैसले को अप्रभावी बना दिया है जिस आधार पर निर्णय लिया गया था।

23. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष तीन निर्णयों का हवाला दिया। पंछी देवी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [(2009) 2 एससीसी 589], पैरा 9 हमारे सामने इस प्रस्ताव के लिए उद्धृत किया गया था कि एक प्रत्यायोजित कानून सामान्यतः भावी प्रकृति का होता है और इसकी व्याख्या उस अधिकार या दायित्व को छीनने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए नहीं की जानी चाहिए जो पहली बार बनाया गया था। वर्तमान मामले में, हम विधायिका के एक अधिनियम से संबंधित हैं न कि प्रत्यायोजित कानून से। कोई भी अधिकार या दायित्व पहली बार नहीं बनाया गया है–वर्तमान मामले में केवल यही किया गया है कि एक फर्म को कानून की कल्पना के अनुसार उसके विघटन के बाद भी मूल्यांकन के कुछ उद्देश्यों के लिए जारी रखा जाता है। समान रूप से, पूर्वव्यापीता की व्याख्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वर्तमान मामले में विधायिका ने स्पष्ट रूप से आक्षेपित प्रावधान को पूर्वव्यापी बना दिया है। इन सभी पहलुओं पर, यह निर्णय अलग है और यहां बिल्कुल भी लागू नहीं होगा।

24. इसके बाद टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(2004) 5 एससीसी 783] के पैरा 12 के आधार पर यह तर्क दिया गया कि एक निर्धारिती को कानून द्वारा उचित रूप से दी गई राहत की पूर्वव्यापी प्रभाव से वापसी, जिसे निर्धारिती ने निहित वैधानिक अधिकार के रूप में कानूनी रूप से आनंद लिया है, तब तक वापस नहीं ली जा सकती जब तक कि उक्त वापसी को उचित ठहराने वाली मजबूत और असाधारण परिस्थितियां न हों। तथ्यों पर फिर से, यह निर्णय लागू नहीं होता है। किसी भी अधिकार की कोई वापसी नहीं है जो एक निहित वैधानिक अधिकार बन गया है जो वर्तमान मामले में निर्धारिती को किसी भी चीज़ से वंचित करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो प्राप्तकर्ता निर्धारिती के हाथों में कर योग्य था, वह अब केवल कुछ उद्देश्यों के लिए विघटन के बाद विघटित फर्म के हाथों कर योग्य है। इसलिए, इस निर्णय का वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।

25. अंत में, हमारे सामने हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [(2006) 8 एससीसी 613] के फैसले का हवाला दिया गया। इसके पैरा 31 को इस प्रस्ताव के समर्थन में पढ़ा गया कि किसी क़ानून में स्पष्टीकरण डालने से, अधिनियम के मुख्य प्रावधान को पराजित या विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इस परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि 1997 में दोनों मुख्य प्रावधान, यानी धारा 26(4) और स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी रूप से जोड़े गए थे। मुख्य प्रावधान को विघटित फर्मों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है और स्पष्टीकरण एक विघटित फर्म को कुछ उद्देश्यों के लिए निर्धारिती के रूप में अस्तित्व में मानकर मुख्य प्रावधान को आगे बढ़ाने में एक कानूनी कल्पना बनाता है। ऐसा होने पर, इस निर्णय का वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

26. इन कारणों से, हम दिनांक 03.07.2002 के आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं।

अपीलों को अनुमत किया गया।

निधि जैन

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी  द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।